



उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून

E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 14 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-07(08/67)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचुला के मांगती, घटियाबगड़ में आई आपदा से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि बरम तक ही हवाई सर्वेक्षण में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया जा सका। मौसम खराब होने के कारण आगे नहीं जा सके। मालपा से घटियाबगड़ तक तीन जगह पर पुल क्षतिग्रस्त हुये है। तवाघाट के पास 150 फुट सड़क बह गयी है। एसडीआरएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सेना की टुकडियां, स्थानीय प्रशासन और लोग राहत व बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। लापता लोगों के बचाव व खोजबीन का कार्य तेजी चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से उनकी फोन पर बात हुई है। उन्होंने राहत और बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ टीम भेजने की बात कही। हालांकी एनडीआरएफ की एक टीम मालपा में बचाव कार्य में जुटी हुई है। नेपाल सीमा होने कारण आपदाग्रस्त क्षेत्र में मोबाईल कनेक्टिविटी की समस्या के बारे में गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। नेपाल सरकार से बातचीत कर मोबाईल सर्विस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है। जिससे नेपाल सीमा से सटे आपदाग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी मिलती रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मौसम की खराबी कारण धारचुला वैली स्थित हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतारने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर ने तीन राउंड लगाये पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में गये दो दल चीन सीमा में सुरक्षित है। एक दल को मानसरोवर यात्रा पर जाना है। सड़कें ठीक होने के बाद ही आगे यात्रा की अनुमति दी जायेगी। इस क्षेत्र में तीन पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा में क्षतिग्रस्त सिंगखोला पुल, जो सिखा व गाला को जोड़ता है को दो दिन में आवागमन के लिये खोल दिया जायेगा। मालपा में नजमगढ़ के पास क्षतिग्रस्त मालपा पुल एक सप्ताह में ठीक कर दिया जायेगा। तवाघाट में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क को आवागमन के लिये खोल दिया गया है। मांगतीनाला में घायल हुये चार जवानों को उपचार के लिये धारचुला लाया जा रहा है। अभी तक 08 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की खोज की जा रही है वहां पर एसडीआरएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सेना के 80 लोग राहत व बचाव कार्य में जुटे हुए है।

मालपा में आई दैवीय आपदा में अब तक मिली जानकारी के अनुसार मृतकों के नाम निम्नवत् है।

1. मालती देवी पत्नी पुष्कर सिंह(दुकानदार)
2. सुरेन्द्र गर्ब्याल पुत्र दलीप सिंह निवासी गर्बियांग
3. जैमल सिंह पुत्र मनवीर सिंह निवासी जिप्ती(दुकानदार)
4. नील बहादुर पुत्र अज्ञात निवासी नेपाल(पोर्टर)

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के मांगती, घटियाबंगड़ एवं मालपा में आयी आपदा एवं विगत दिनों जनपद के सीमांत क्षेत्र बरम, दूंगातोली, मदरमा एवं तहसील बंगापानी के मदरमा में आयी आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में जिला प्रशासन से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जनपद पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने नैनीसैनी हवाई पट्टी में जिला प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की कौताही न बरती जाए। आपदा प्रभावितों को खाद्यान्न एवं शुद्ध पेयजल आदि आवश्यक सामग्रियों की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों हेतु हर सम्भव मदद दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि लापता हुए व्यक्तियों की खोज एवं बचाव के कार्यों में तेजी लाई जाए। जो भी सड़क मार्ग अवरूद्ध है, उन्हें तुरन्त खोले जाने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि आपदा की दृष्टिगत सीमांत क्षेत्र धारचूला में एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रहे। जिला प्रशासन आपदा एवं मानसून काल में हाई अलर्ट में रहे एवं किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए तैयार रहे।

निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत, विधायक डीडीहाट श्री बिशन सिंह चुफाल, विधायक गंगोलीहाट श्रीमती मीना गंगोला, जिलाधिकारी सी.रविशंकर, जिला प्रशासन के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

नोट : जिला सूचना कार्यालय पिथौरागढ़ से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के उन सभी ज्ञात और अज्ञात शूरवीरों को श्रद्धापूर्वक नमन किया है, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया, अनेक यातनाएं सही, यहां तक कि अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीदों और आन्दोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया है।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों के नाम जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि आजादी के इन 70 वर्षों में हमारा लोकतंत्र न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के सतत् विकास के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जिन्हें 2022 तक पूरा किया जायेगा। इनमें 2022 तक प्रत्येक जिले की प्रति व्यक्ति आय और किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। 2022 तक हर बेघर को आवास मुहैया कराना, सभी बसावटों को पीने का पानी उपलब्ध कराना, मातृ-मृत्यु दर और शिशु-मृत्यु दर में कमी लाना, हर गांव को सड़क से जोड़ना तथा 5 लाख बेरोजगार युवक युवतियों को स्किल करना है। 2019 तक हर घर तक बिजली पहुंचाना तथा 100 फीसदी साक्षरता दर हासिल करना है। इन सब लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा है कि उन्होंने आजादी के पर्व पर राज्यहित में मैने संकल्प लिया है कि राज्य को भ्रष्टाचार से आजादी, नशे से आजादी, गंदगी से आजादी, एक वृक्ष लगाने का संकल्प और पानी को बचाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प से सभी प्रदेशवासी जुड़े, ताकि हम एक आदर्श, सुशासन और विकसित उत्तराखण्ड के सपने को साकार कर सकें।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, जहां किसी को भी भ्रष्टाचार करने का मौका ही न मिले। इसके लिए पुरस्कार और दंड दोनों ही नीतियां अपनायी जायेंगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की रिव्यू, मॉनीटरिंग एवं फॉलोअप हेतु सी.एम. डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार एक स्थायी भ्रष्टाचार जांच आयोग का गठन करने जा रही है, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच करेगा और दोषियों को दंड मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सुशासन एवं सुनियोजित विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए "सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स" का गठन किया है। समाधान पोर्टल के अंतर्गत पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को आईवीआरएस से कनेक्ट किया गया है, जिससे आम जनता द्वारा फोन व सोशल साइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। सभी विभागों को सिटीजन चार्टर तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। सेवा के अधिकार को और सशक्त किया गया है इसकी प्रतिमाह मॉनिटरिंग की जा रही है। विभागों के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि राज्य के बहुआयामी विकास एवं भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन के लिए सभी अपना योगदान दें। सुराज सिर्फ सरकार के प्रयासों से नहीं आता, इसके लिए जन-सहभागिता की जरूरत भी होगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में खोले गये स्कूलों की क्लबिंग कर उनकी क्षमता वृद्धि और मॉडल आवसीय विद्यालयों की स्थापना हमारी प्राथमिकता है। कक्षा 01 से 12 तक के विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में एन.सी.आर.टी. की पुस्तकों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि केन्द्र सरकार ने हमें तीन बड़े शिक्षण संस्थानों से नवाजा है। ये हैं NIFT (National Institute of fashion technology), Hospitality University और सीपैट (CIPEAT) यानि Central institute of plastic engineering and advanced Technology जिनसे प्रदेश के युवाओं को नये अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सेना के रिटायर डाक्टरों की सेवाएं लेने पर भी सहमति बन गई है। राज्य के 6 अस्पताल ई-अस्पताल के रूप में काम करने लगे हैं और जल्द ही बाकियों को भी ई-अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। साथ ही टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञों का परामर्श मिल सके। राज्य सरकार बीपीएल और आयकर के दायरे में न आने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। जनसामान्य को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 100 प्रधानमंत्री जन औषधी केन्द्र खोले जा रहें हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को केन्द्र की योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं मिला, उन्हें राज्य सरकार की ओर से गैस कनेक्शन दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया है। उत्तराखण्डवासियों को प्रदेश के विकास से जोड़ने के लिए प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया जायेगा। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक लाख युवाओं को स्किल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया के लिए स्किल उत्तराखंड की सोच को बढ़ाना होगा। उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जल संचय एवं संवर्द्धन के लिए प्रत्येक जनपद में कम से कम एक नदी या बड़े जल स्रोत को प्रदूषण मुक्त एवं पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसानों के हित में विभागों का एकीकरण किया जाएगा। जल्द ही सरकार पौधशाला अधिनियम बनाने जा रही है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए कई कृषि जीन्स का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्लस्टर आधारित खेती को आगे बढ़ाया जाएगा।

अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रदेश वासियों से आग्रह किया कि उत्तराखंड को स्वच्छ प्रदेश बनाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। हमें हफ्ते में कुछ समय स्वच्छता के लिए लगाना होगा। जो प्रदेश पर्यटन का केन्द्र हो, वहां गंदगी का क्या काम। इसलिए जरूरी है कि सब साथ मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच से मुक्त होने वाला चौथा ओडीएफ राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्र को भी मार्च, 2018 तक ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, सामाजिक सहित सभी क्षेत्रों में एक ठोस कार्ययोजना के तहत कार्य कर रही है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों से उत्तराखण्ड के विकास में अपना सक्रिय योगदान देने की अपील की है।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।

देहरादून 14 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-04(08/64)

राज्यपाल डॉ.कृष्णाकांत पाल ने जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के अन्तर्गत मागती नाला (तवाघाट) एवं मालपा में अतिवृष्टि/भूस्खलन में मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है।

देहरादून 14 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-03(08/63)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के अन्तर्गत मागती नाला (तवाघाट) एवं मालपा में अतिवृष्टि/भूस्खलन में मृतकों के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने जिला प्रशासन को तत्काल मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को अनुमन्य राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

देहरादून 14 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-02(08/62)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में वर्ल्ड पुलिस एण्ड फॉयर गेम्स-2017 में बॉडी बिल्डिंग में पुलिस के आरक्षी श्री तेजेन्द्र द्वारा स्वर्ण पदक एवं पावर लिफ्टिंग में मुकेश पाल द्वारा कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।

हल्द्वानी/देहरादून 14 अगस्त, 2017(सू.ब्यूरो)

प्रेस नोट-01(08/61)

बीते रविवार को देर रात सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में हो रही वर्षा के बाद धारचूला के ग्राम ढूगातोली में हुई भारी बारिश के बाद हुये भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा वित्तमंत्री श्री प्रकाश पंत सोमवार की दोपहर प्रभावी क्षेत्रों का जायजा लेने रवाना हुये। मुख्यमंत्री श्री रावत कुछ समय के लिए हल्द्वानी स्थित आर्मी हेलीपैड पर रुके। अल्प विश्राम के बाद उन्होंने वित्तमंत्री के साथ पिथौरागढ़ के प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करने के लिए रूख किया।

हल्द्वानी अल्प विश्राम के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि मौसम की चेतावनी के चलते आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। मौसम की चेतावनी के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट रहता है। इसके चलते बीती रात धारचूला के ग्राम ढूगातोली में हुई तबाही में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ही एसडीआरफ के जवान मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। श्री रावत ने कहा कि सीमान्त जनपद का धारचूला एवं मुनस्यारी इलाका आपदा के मामले में काफी संवेदनशील है इन क्षेत्रों में आपदाओं के नियंत्रण एवं भूस्खलन जैसी समस्याओं के स्थायी निराकरण के लिए सचिव आपदा प्रबंधन को कारणों का पता लगाये जाने तथा स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार के सहयोग से इन क्षेत्रों में स्थायी समाधान किये जाने की दिशा में प्रदेश सरकार कार्य करेगी।

वित्तमंत्री श्री पंत ने कहा कि विगत देर रात आपदा की जानकारी सरकार को मिल गई थी। स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ के जवानों द्वारा तत्काल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। घायलो एवं प्रभावित लोगो को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये जाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। श्री पंत ने बताया कि मालपा से गाल तक का मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। लमाडी-चूडी मार्ग में भी काफी दिक्कत है। इन मार्गों को तत्काल खोले जाने के लिए कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इसके साथ ही व्यासघाटी में पूजा अर्चना करने वाले दर्शनार्थी व अन्य लोगों के भी फंसे होने की जानकारी मिल रही है। इन सभी को सुरक्षित निकाले जाने के लिए हैली सेवाओं की मदद ली जा रही है।

नोट : मीडिया सेंटर, हल्द्वानी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।